बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 228 ● नई दिल्ली ● शनिवार 27 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली के मुंडका में बड़ा हादसा, फैक्टरी के सेप्टिक टैंक में उतरे 3 सफाईकर्मियों की जहरीली गैस से मौत

नई दिल्ली । देश की राजधानी दिल्ली के मुंडका औद्योगिक इलाके से एक बेहद दुखद और दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां आज दोपहर एक फैक्टरी के सेप्टिक टैंक (गटर) की सफाई करने उतरे 3 लोगों की जहरीली गैस की चपेट में आने से दम घुटने के कारण मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर शवों को बाहर निकाला। अधिकारी के मुताबिक दोपहर करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि मुंडका औद्योगिक इलाके में सेप्टिक टैंक में कुछ लोग फंस गए है जिसके बाद एक टीम को मौके पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि तीन लोग एक-एक करके सेप्टिक टैंक में उतरे थे और वे जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गए।

ड्रग माफियाओं पर बड़ा प्रहार - अमित शाह ने जारी किया नया रोडमैप, छह हजार करोड़ के नशीले पदार्थ किए गए नष्ट

नई दिल्ली ।

देश में नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ केंद्र सरकार अपनी कार्रवाई को और तेज करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की की। इस दौरान उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 जारी किया। इससे देश को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए अगले तीन वर्षों का रोडमैप तय किया गया। बैठक में केंद्र और राय सरकारों के साथ विभिन्न जांच एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। गृह मंत्रालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देशभर में ड्रग तस्करी और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ चल रहे अभियानों की समीक्षा करना और उन्हें और मजबूत बनाना है। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों, राय सरकारों और ड्रग कानून लागू करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सरकार का कहना है कि ड्रग्स के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति को और प्रभावी बनाने के लिए सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। सभी संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों को एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगले एक वर्ष में किसी भी सूचकांक (इंडिकेटर) में गिरावट नहीं आनी चाहिए। हर मानक में उल्लेखनीय सुधार होना चाहिए और

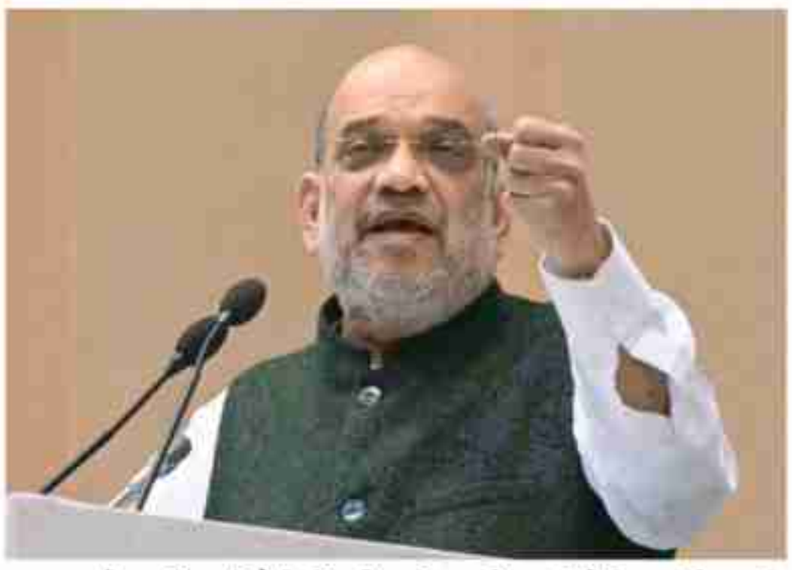

यह अगले वार्षिक रिपोर्ट में भी दिखाई देना चाहिए। नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई खुफिया जानकारी (इंटेलिजेंस) आधारित होनी चाहिए। ड्रग तस्करी से निपटने के लिए नेटवर्क-केंद्रित (नेटवर्क-सेंट्रिक) रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। नशे के कारोबार के खिलाफ लड़ाई में कठोर और निर्दयी रवैया अपनाना जरूरी है। केवल सख्त और समन्वित कार्रवाई के जरिए ही इस चुनौती पर विजय हासिल की जा सकती है।

नए विजन डॉक्यूमेंट में क्या खास?

नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 में नशीले पदार्थों की मांग कम करने, तस्करी की सप्लाई चेन तोड़ने और नशे के शिकार लोगों के पुनर्वास पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही यह दस्तावेज आने वाले वर्षों में ड्रग्स के खिलाफ राष्ट्रीय रणनीति का आधार बनेगा। विजन डॉक्यूमेंट में नई चुनौतियों से निपटने की रणनीति भी शामिल की गई है। इनमें सिंथेटिक ड्रग्स का बढ़ता इस्तेमाल और डार्कनेट के जरिए हो रही ड्रग तस्करी प्रमुख हैं। इसके अलावा, नशे से प्रभावित लोगों के लिए जागरूकता अभियान, इलाज की सुविधाएं और पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया गया है।

छह हजार करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ क्यों नष्ट किए?

गृह मंत्री ने इस दौरान ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट कैंपेन की भी शुरुआत की। इस अभियान के तहत देशभर में जब्त किए गए लगभग 2,09,500 किलोग्राम नशीले पदार्थों को कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया। इन नशीले पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 6,000 करोड़ रुपये बताई गई है। सरकार का मानना है कि यह अभियान ड्रग तस्करी के नेटवर्क को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाएगा।

सीबीएसई का बड़ा फैसला - 7वीं-9वीं तक के छात्रों पर अभी नहीं लागू होगी नई भाषा नीति, 10वीं तक पुराने नियम ही रहेंगे

नई दिल्ली । केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, वर्तमान में कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे वे छात्र जिन्होंने तीन-भाषा नीति के तहत दो विदेशी भाषाओं का चयन किया है, वे कक्षा 10 तक उसी भाषा संयोजन के साथ पढ़ाई जारी रख सकेंगे। उन्हें बीच में अपने विषय बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। सूत्रों ने बताया कि तीन-भाषा नीति के तहत कम से कम दो भारतीय भाषाएं पढ़ने की अनिवार्यता केवल आगे आने वाले छात्रों पर लागू होगी। यह व्यवस्था कक्षा 6 से भविष्य के बैचों के लिए लागू की जाएगी। पहले से कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे छात्रों पर इसे पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा।

सरकार ने कहा- यह यू-टर्न नहीं, सिर्फ स्पष्टता

शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह फैसला किसी तरह की नीति में बदलाव या पीछे हटना नहीं है। उनके अनुसार, यह

प्रावधान पहले भी मौजूद था, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था। अब छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम दूर करने के लिए स्थिति साफ की गई है।

केवल कुछ हजार छात्र ही होंगे प्रभावित

मंत्रालय के अनुसार, हर साल लगभग 24 लाख छात्र सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होते हैं। इनमें से करीब 30 हजार छात्र ही दो विदेशी भाषाओं का विकल्प चुनते हैं। यानी लगभग 98.5 प्रतिशत छात्र पहले से ही तीन-भाषा फॉर्मूले का पालन कर रहे हैं। यह राहत मुख्य रूप से महानगरों और शहरी क्षेत्रों के उन छात्रों के लिए दी गई है, जिन्होंने पहले से दो विदेशी भाषाएं चुनी थीं।

मई के सर्कुलर के बाद शुरू हुआ था विवाद

गौरतलब है कि मई 2026 में सीबीएसई ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के तहत एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें कहा गया था कि 2026-27 सत्र से कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं शामिल हों। इस फैसले के बाद कई छात्रों और अभिभावकों ने विरोध जताया था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया था इनकार

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने इन याचिकाओं को पहले से लंबित समान मामलों के साथ जोड़ने का निर्देश दिया था।

जल्द जारी होगा आधिकारिक आदेश

शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस स्पष्टीकरण को शामिल करते हुए औपचारिक आदेश जल्द जारी किए जाएंगे, ताकि स्कूलों और छात्रों के बीच किसी तरह की भ्रम की स्थिति न रहे।

मनाया गया छत्रपति शाहू जी महाराज का जन्म दिवस

आनंदनगर महराजगंज। ग्रीन वैली होटल फरेंदा में कुर्मी क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष विनोद चौधरी के अध्यक्षता में आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महराज का जन्म दिवस उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष विनोद चौधरी नेकहा कि छत्रपति शाहूजी महाराज ने दबे कुचले गरीब असहाय लोगों की लड़ाई हमेशा लड़ी और उनके उत्थान के लिए आरक्षण की मांग की तथा उनके द्वारा समाज में सामाजिक समरसता बनाए रखने हेतु सदैव कार्य किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के सम्मानित साथियों के साथ जिला महांमत्री त्रिपुरेश प्रताप सिंह, पिंटू , संगठन के जिला संरक्षक प्रमोद चौधरी, देवेश चौधरी, परमहंश चौधरी, आशीष चौधरी, भगवंत पटेल , राजकुमार चौधरी ,आर पी यादव , सहित क्षेत्र के तमाम साथी उपस्थित रहे।

डीडीए की कार्रवाई से बेघर हुए नाविक - यमुना के साथ बहता रोजगार, नाविकों की विरासत और रोजी पर मंडराया खतरा

नई दिल्ली । यमुना बाजार इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद वहां रहने वाले नाविक समुदाय के सामने सिर्फ घर खोने का संकट नहीं है, बल्कि उनकी पीढ़ियों पुरानी आजीविका भी खतरे में पड़ गई है। यमुना के फ्लडप्लेन क्षेत्र में बसे ये परिवार दशकों से नाव चलाने, धार्मिक अनुष्ठानों और तीर्थयात्रियों को नदी पार कराने का काम करते आए हैं। गुरुवार को कार्रवाई के दौरान बुलडोजर ने घाट नंबर 2 और 32 के बीच बसी झुग्गियों और अस्थायी ढांचों को हटा दिया। इससे कई परिवार बेघर हो गए और उन्हें पास के शेल्टर होम की ओर जाना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार, लगभग 100 से अधिक परिवार इस कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं। नाविक समुदाय से आने वाले रमेश कुमार ने बताया कि यमुना उनके लिए सिर्फ नदी नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। वे पीढ़ियों से इसी नदी पर निर्भर हैं। उनका परिवार करीब 150 से 200 साल से इसी काम में लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि नदी से दूर जाकर वे अपना काम जारी नहीं रख सकते। नाविक सुधाकर कुमार निषाद ने बताया कि वे सुबह से घटनास्थल पर स्थिति देख रहे हैं। उनके अनुसार, उनकी नाव ही उनकी एकमात्र संपत्ति है, जिससे उनका पूरा परिवार चलता है। अब उनके बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि प्रशासन ने कुछ दिन पहले यमुना फ्लडप्लेन क्षेत्र को खाली करने का नोटिस दिया था। इसके बाद 24 जून को कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि यह इलाका यमुना के 'ओ-जोन' फ्लडप्लेन का हिस्सा है, जहां निर्माण प्रतिबंधित है। हालांकि, प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्हें सिर्फ जगह खाली करने को कहा गया, लेकिन आजीविका के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बताई गई।

ब्लैक इमरजेंसी डे पर बोलीं सीएम रेखा गुप्ता-लोकतंत्र उनका गुलाम नहीं; सुधांशु त्रिवेदी ने गिनाए गलत फैसले

नई दिल्ली।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को ब्लैक इमरजेंसी डे सेमिनार को संबोधित करते हुए इमरजेंसी की भयावह यादों को ताजा किया और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। वहीं, भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के गलत फैसलों के बारे में संज्ञान लिया।

संविधान उनकी जेब में नहीं

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, आज यह बेहद विडंबनापूर्ण है कि वे लोग जो संविधान की कॉपी जेब में रखकर घूमते हैं और हर मंच पर लोकतंत्र पर हमले की बात करते हैं। रैली हो या टीवी चैनल, वे संविधान निकालकर कहते हैं कि इसके प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा। वे समझते है कि संविधान उनकी जेब में है। लेकिन संविधान उनकी जेब में नहीं है और लोकतंत्र उनका गुलाम भी नहीं है।

अटल बिहारी और जेपी को किया याद

उन्होंने आगे कहा, जब वे जेल में थे, तब भारत के हर लोकतंत्र रक्षक ने उन्हें यही संदेश दिया था। किसी की हिम्मत नहीं टूटी। जयप्रकाश नारायण शारीरिक रूप से जंजीरों में जकड़े गए, लेकिन उनकी हिम्मत कभी नहीं बंधी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जेल में भी अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल जारी रखा। हमने यह सब खुद देखा है। बता दें कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब देशभर में इमरजेंसी की 51वीं वर्षगांठ पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

'ब्लैक इमरजेंसी डे' का आयोजन

यह कार्यक्रम 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी की 51वीं बरसी पर आयोजित किया गया। भाजपा और सहयोगी संगठन इमरजेंसी की याद में हर साल 25 जून को 'ब्लैक इमरजेंसी डे' मनाते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र को कुचला गया था, लेकिन जनता की एकजुटता और नेताओं के अटूट संकल्प ने इसे वापस बहाल किया।

मुस्लिम लीग पर घेरा

वहीं, पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कल भारतीय लोकतंत्र के सबसे अंधकारमय अध्याय यानी इमरजेंसी को याद करने के बाद, आज कांग्रेस पार्टी के इतिहास में आत्मसमर्पण का एक और काला अध्याय है। यह आत्मसमर्पण मुस्लिम लीग के आगे झुकने से शुरू हुआ, जिसके कारण 1947 में पाकिस्तान का निर्माण हुआ।

अक्साई चीन की दिलाई याद

उन्होंने कहा कि इसके बाद कांग्रेस ने पाकिस्तान को पीओके सौंप दिया, चीन को अक्साई चिन दे दिया और लगभग असम तथा मानसरोवर को भी चीन को सौंपने ही वाली थी। इसी दिन 26 जून 1974 को कांग्रेस सरकार ने श्रीलंका को कचातिवु द्वीप सौंप दिया। इस फैसले से पहले किसी भी हितधारक को विश्वास में नहीं लिया गया।

भारतीयों मछुआरों का बताया दर्द

त्रिवेदी ने कहा, इसी के कारण आज भी भारतीय मछुआरे भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

यहां तक कि कैथोलिक समुदाय के लोग जो द्वीप पर सेंट एंथनी के मंदिर में पूजा-अर्चना करने जाते हैं, उन्हें अपनी नावों पर भारतीय झंडा लगाने की भी अनुमति नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस ने अपने पूरे शासनकाल में लगातार भारत के राष्ट्रीय हितों को कैसे सौंपा और कुर्बान किया।

सम्पादकीय...

25 जून 1975

25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की उन तिथियों में शामिल है, जिसे आज भी लोकतांत्रिक मूल्यों की सबसे बड़ी परीक्षा के रूप में याद किया जाता है। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आंतरिक आपातकाल लागू किया था। 21 महीनों तक चले इस दौर में नागरिक स्वतंत्रताओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर गंभीर प्रश्न उठे। 25 जून 2026 को आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने इसे भारतीय संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया तथा इस अवसर को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी संदेश में कहा कि आपातकाल भारतीय संविधान पर प्रत्यक्ष आघात था। उनके अनुसार इस दौरान नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई और लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाने वाली संस्थाओं पर हमला हुआ। उन्होंने उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने इस कठिन दौर में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, अधिकारों और कर्तव्यों का प्रतीक है तथा भारत न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक आदर्शों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस अवसर पर कांग्रेस की तीखी आलोचना की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला करने वाली कांग्रेस आज स्वयं को संविधान की सबसे बड़ी रक्षक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। उनका आरोप था कि जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो वह चुनाव आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं पर प्रश्न उठाती है। उन्होंने यह भी पूछा कि कांग्रेस ने आज तक आपातकाल लागू करने के लिए देश से बिना शर्त माफी क्यों नहीं मांगी। आपातकाल की पृष्ठभूमि भी भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण अध्याय है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली से हुए चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था। इसके बाद राजनीतिक संकट गहराया और 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। सरकार का तर्क था कि देश की आंतरिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक था, जबकि विपक्ष ने इसे सत्ता बचाने का प्रयास बताया। इस अवधि में अनेक प्रमुख विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी सहित हजारों राजनीतिक कार्यकर्ता जेल भेजे गए। प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई और सरकार की आलोचना करने वाली खबरों को प्रकाशित करने पर रोक लगा दी गई। अनेक नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र अभिव्यक्ति और राजनीतिक विरोध की जो परंपरा रही थी, वह गंभीर रूप से प्रभावित हुई। भाजपा का कहना है कि इस दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनसंघ तथा अन्य विपक्षी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भूमिगत रहकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दावा किया कि युवा कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय युवा नरेंद्र मोदी गिरफ्तारी से बचते हुए वेश बदलकर लोकतांत्रिक आंदोलन का संदेश लोगों तक पहुंचाते रहे। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने आपातकाल के दौरान हुए संवैधानिक परिवर्तनों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संसद का कार्यकाल पांच वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष कर दिया गया और विपक्षी नेताओं के जेल में होने के दौरान 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इसी संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में पूर्व प्रभाव से संशोधन कर प्रधानमंत्री के चुनाव को कानूनी चुनौती से बचाने का प्रयास किया। हालांकि, आपातकाल को लेकर भारतीय राजनीति में अलग-अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं। कांग्रेस का कहना रहा है कि उस समय देश असाधारण परिस्थितियों से गुजर रहा था और सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत निर्णय लिया था।

दूसरी ओर, पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने समय-समय पर स्वीकार किया है कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का ऐसा अध्याय था, जिससे महत्वपूर्ण सबक लेने की आवश्यकता है। यही कारण है कि आज भी यह विषय राजनीतिक और ऐतिहासिक बहस का केंद्र बना हुआ है। आपातकाल का सबसे बड़ा संदेश यह है कि लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता। उसकी वास्तविक शक्ति स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव आयोग, स्वतंत्र मीडिया, सक्रिय विपक्ष और जागरूक नागरिक समाज में निहित होती है।

जब इन संस्थाओं की स्वतंत्रता कमजोर होती है, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था भी संकट में पड़ सकती है। इसलिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें। आज, आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ पर यह अवसर केवल अतीत को याद करने का नहीं, बल्कि लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने का भी है। इतिहास का उद्देश्य केवल घटनाओं का स्मरण करना नहीं, बल्कि उनसे सीख लेकर भविष्य को बेहतर बनाना है। भारत का लोकतंत्र अनेक चुनौतियों के बावजूद लगातार विकसित हुआ है और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों का सम्मान और संविधान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ही वह आधार है, जिन पर एक सशक्त और समावेशी भारत का निर्माण संभव है।

मेसी द अल्टीमेट किंग

लियोनेल आंद्रेस मेसी केवल एक फुटबॉलर नहीं, बल्कि आधुनिक फुटबॉल का प्रतीक हैं। उनकी कहानी संघर्ष, प्रतिभा, अनुशासन, विनम्रता और निरंतरता की मिसाल है। अर्जेंटीना के रोसारियो शहर की तंग गलियों से निकलकर दुनिया के सबसे महान फुटबॉलरों में गिने जाने तक का उनका सफर असाधारण है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल दागकर लियोनेल मेसी ने पुरुषों के वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक 18 गोल का नया रिकॉर्ड बनाया, जिससे क्लोज़ को पीछे छोड़ दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बावजूद मेसी ने रिकॉर्ड्स पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वर्तमान पल का आनंद लेने और अपनी टीम की आगे की यात्रा पर ज़ोर दिया है। मेसी ने दो गोल किए और अपने 39वें जन्मदिन (24 जून) से पहले पुरुषों के वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रिया के खिलाफ़ अपनी टीम की शानदार 2-0 की जीत में उन्होंने क्लोज़े को पीछे छोड़ दिया। मेसी पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में टूर्नामेंट के तीन अलग-अलग संस्करणों (2014, 2022 और 2026) में चार या उससे ज्यादा गोल करने वाले सिर्फ़ दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। यह कारनामा करने वाले एकमात्र दूसरे खिलाड़ी क्लोज़ हैं। दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में गिने जाने वाले मेसी के कैरियर का सफर मुश्किलों भरा रहा है। 13 वर्ष की उम्र में मेसी अपने परिवार के साथ स्पेन चले गए। बार्सिलोना की ला मासिया अकादमी में उन्होंने प्रशिक्षण शुरू किया। नई भाषा, नई संस्कृति और घर से दूर रहना आसान नहीं था, लेकिन मेसी ने मैदान पर अपने खेल से सबका दिल जीत लिया। बार्सिलोना ने उनके इलाज का पूरा खर्च उठाया और उन्हें युवा टीमों में शामिल किया। उनकी तेजी, तकनीक और गोल स्कोरिंग क्षमता ने उन्हें जल्दी ही अलग पहचान दिला दी। पेशेवर करियर की शुरुआत- मेसी ने 2004 में 17 वर्ष की उम्र में बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए पदार्पण किया। जल्द ही वे टीम के अहम खिलाड़ी बन गए। 2005-06 सीजन में उन्होंने अपने पहले ला लीगा गोल किए और टीम के साथ ट्रॉफी जीती। उनकी जोड़ी रोनाल्डिन्हो के साथ शानदार रही। 2008 में पेप गार्डियोला के कोच बनने के बाद मेसी का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। 'फॉल्स नाइन' की भूमिका में उन्होंने फुटबॉल की परिभाषा बदल दी। 2009 में बार्सिलोना ने ऐतिहासिक 'सेक्सटुपल' (छह खिताब) जीते। मेसी ने लगातार गोलों और असिस्ट्स में रिकॉर्ड तोड़े। 2012 में उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 91 गोल कर इतिहास रच दिया। व्यक्तिगत रिकॉर्ड और बैलन डी'ओर- मेसी ने अपने करियर में कई रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने कई बार बैलन डी'ओर जीता और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। लियोनेल मेसी और नैपकिन का संबंध उनके फुटबॉल करियर के सबसे ऐतिहासिक और प्रसिद्ध किस्सों में से एक है। 14 दिसंबर 2000 को, बार्सिलोना के तत्कालीन स्पोर्ट्स डायरेक्टर कार्ल्स रेक्साच ने सिर्फ 13 साल के मेसी के साथ एफसी बार्सिलोना के लिए एक अनौपचारिक अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) एक सामान्य पेपर नैपकिन पर ही लिखकर किया था। जब मेसी के पिता और एजेंट स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के अधिकारियों से कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातचीत कर रहे थे तो अधिकारी कोई ठोस निर्णय नहीं ले रहे थे। इससे निराश होकर मेस्सी के पिता उन्हें वापस अर्जेंटीना ले जाने वाले थे। स्थिति को संभालते हुए बार्सिलोना के डायरेक्टर कार्ल्स रेक्साच ने मेसी के टैलेंट पर भरोसा जताया और उन्हें तुरंत साइन करने का फैसला किया। उस समय पास में कोई आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट पेपर उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट के नैपकिन पर ही नीली स्याही से करार लिख दिया। उस नैपकिन पर कार्ल्स रेक्साच, होरासियो गैगिओली और जोसेफ मिंगुएला ने हस्ताक्षर किए थे। इस छोटे से वादे और नैपकिन के जरिए मेसी बार्सिलोना से जुड़े। इसके कुछ दिन बाद एक औपचारिक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया, इसके बाद मेसी ने क्लब के लिए कई रिकॉर्ड तोड़े। फुटबॉल के इतिहास का रुख बदलने वाले उस नैपकिन को साल 2024 में लंदन की नीलामी संस्था बोनहैम्स द्वारा नीलाम किया गया। इस नैपकिन को लगभग 762,400 पाउंड (यानी करीब 8 करोड़ रुपये से अधिक) की भारी कीमत पर एक अज्ञात खरीदार द्वारा खरीदा गया। इसके अलावा, मेसी से जुड़े नैपकिन का एक और किस्सा भी काफी चर्चा में रहा था।साल 2021 में, जब मेसी ने एफसी बार्सिलोना छोड़ने की घोषणा करते हुए अपनी विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसू पोंछे थे तो उस टिश्यू पेपर (नैपकिन) की भी ऑनलाइन नीलामी में 10 लाख डॉलर (करीब 8 करोड़ रुपये) तक की कीमत लगाई गई थी फोर्ब्स के मुताबिक लियोनेल मेसी की कुल नेट वर्थ 1.1 बिलियन यूएस डॉलर है। जबकि उनकी सैलरी की बात करें तो 140 मिलियन यूएस डॉलर है। मेसी कभी नहीं भूले कि मदद की जरूरत कैसी होती है। 2007 में उन्होंने लियो मेस्सी फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मुश्किल समय से गुजर रहे बच्चों, विशेषकर कैंसर से जूझ रहे बच्चों की मदद करना था। उनका लक्ष्य अपनी प्रसिद्धि का उपयोग जरूरतमंदों को प्रेरित करने और उनकी सहायता करने के लिए करना था। फाउंडेशन की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक बार्सिलोना में स्थित एसजेडी पीडियाट्रिक कैंसर सेंटर के साथ उसका सहयोग रहा है। मेसी के फाउंडेशन ने स्टावरोस नियार्चोस फाउंडेशन के साथ मिलकर सेंटर के निर्माण के लिए आवश्यक 30 मिलियन यूरो की धनराशि को पूरा करने के लिए 2.6 मिलियन यूरो का दान दिया। यह सुविधा यूरोप का सबसे बड़ा बाल चिकित्सा कैंसर केंद्र बनने जा रही है, जो प्रतिवर्ष 400 रोगियों का इलाज करने में सक्षम होगा। यह पहल गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों और परिवारों की सहायता के प्रति मेसी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। लियोनेल मेसी की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वे साबित करते हैं कि प्रतिभा के साथ संघर्ष, विनम्रता और मेहनत हो तो असंभव भी संभव हो जाता है।

बिगड़ते बच्चे

सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए आसानी से उपलब्ध अश्लील सामग्री चिंता का विषय है। पिछले दिनों आगरा से सामने आए एक मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि बच्चों के लिए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कितने सुरक्षित हैं। वहां के फतेहाबाद रोड इलाके की रहने वाली एक महिला ने एक प्रचलित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट देखने के बाद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का कहना था कि उनके बच्चे मोबाइल पर रील्स देख रहे थे, तभी अचानक एक ऐसी रील सामने आ गई, जिसमें अश्लील और डबल मीनिंग कंटेंट था, जिसे देखकर बच्चे असहज और परेशान हो गए। जब महिला ने खुद वह वीडियो देखा, तो वह काफी विचलित हो गईं। इस महिला का मानना है कि इस तरह का कंटेंट बच्चों के मानसिक विकास और पारिवारिक माहौल दोनों के लिए खतरनाक है। आजकल हमारे आसपास यही कुछ हो रहा है, बच्चा मां-बाप को तंग करने लगे तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दो, उसे रील चलाने दो, चाहे उसमें अश्लील फिल्म ही क्यों न चलने लगे। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने हमारे लिए एक तरफ जहां जानकारी का भंडार खोल दिया है, वहीं इस पर बच्चों के लिए खुले तौर पर उपलब्ध अवांछनीय सामग्री से सांस्कृतिक खतरे भी तेजी से बढ़े हैं। हाल ही में एक सर्वे में भारतीय माता-पिता की एक गंभीर समस्या सामने आई। इस सर्वे के मुताबिक, देश में 300 से ज्यादा शहरों में हर दूसरे पैरेंट्स का मानना है कि उनके बच्चों ने इंटरनेट पर या तो गलत कंटेंट देखा है या साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं। इंटरनेट पर बुलिंग और गलत कंटेंट के एक्सपोजर का बच्चों के मानसिक और व्यावहारिक विकास पर काफी गहरा असर पड़ रहा है। इंटरनेट पर उपलब्ध हिंसक गेम्स या वीडियो बच्चों के दिमाग को इस कदर प्रभावित करते हैं कि वे असल जिंदगी में भी बात-बात पर गुस्सा करने लगते हैं। सर्वे में भी यह बात सामने आई है कि बच्चों का व्यवहार पहले की तुलना में ज्यादा आक्रामक हुआ है। वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोने लगते हैं। साइबर बुलिंग (अर्थात इंटरनेट, सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स या अन्य डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को डराने, धमकाने, नीचा दिखाने या परेशान करने की ऑनलाइन प्रक्रिया) का शिकार होने पर बच्चे अक्सर हीन भावना से भर जाते हैं। उन्हें डर होता है कि बाहर जाने पर लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें दोबारा निशाना बनाया जाएगा। इस डर के कारण वे खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और परिवार व दोस्तों से दूर होकर अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। ऑनलाइन डराए-धमकाए जाने के कारण बच्चों में नींद न आना, भूख की कमी और पढ़ाई में मन न लगने जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। लंबे समय तक यह स्थिति रहने पर वे एंग्जाइटी या डिप्रेशन की ओर बढ़ सकते हैं। आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। खासकर 13 से 18 साल के बच्चे सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया अदालत में मेटा ने बड़ा खुलासा किया। सोशल मीडिया पर 13-15 साल के करीब 20 प्रतिशत बच्चे ऐसी न्यूड और अश्लील तस्वीरें देख रहे हैं, जिन्हें वे देखना नहीं चाहते। कंपनी की रिसर्च के मुताबिक, यह कंटेंट बिना मांगे बच्चों के सामने आता है। एल्गोरिदम की वजह से ऐसे फोटो बार-बार दिखाई देते हैं।

देश के वास्तविक मुद्दों और भविष्य की दिशा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है

अगर कोई एक सवाल है जो हर विवेकशील व्यक्ति के सामने खड़ा है, तो वह है 'आखिर यह हुआ कैसे या फिर इन लोगों के साथ समस्या क्या है?' यहां 'इन लोगों' से आशय दो व्यक्तियों से है एक अमेरिका में और दूसरा भारत में। एक किसी देश का राष्ट्रपति है और दूसरा एक राजनीतिक दल का वास्तविक नेतृत्वकर्ता। ये दो नाम है, डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी।

आइए शुरुआत करते है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर प्रशंसा करते हुए संबंधों में नरमी का संकेत दिया। यह वही संबंध थे, जिनमें पिछले वर्ष उस समय खटास आ गई थी जब ट्रंप ने भारत पर भारी शुल्क (टैरिफ) लगा दिए थे। उसी वर्ष ट्रंप की भारत यात्रा प्रस्तावित थी, लेकिन बढ़ते तनाव के कारण यह यात्रा रद्द हो गई। टैरिफ के अलावा कई अन्य मुद्दों ने भी तनाव बढ़ाया। इनमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ युद्धविराम भी शामिल था, जिसका श्रेय ट्रंप ने दोनों देशों के बीच संघर्ष रोकने के लिए खुद लिया था। भारत के इस स्पष्ट बयान कि युद्धविराम में किसी तीसरे पक्ष की कोई मध्यस्थता नहीं थी, से ट्रंप नाराज हुए और इसके बाद भारत-अमेरिका संबंधों में दूरी और बढ़ गई। इसके अलावा ब्राजील और चीन के साथ भारत की बढ़ती निकटता ने भी उस गर्मजोशी को प्रभावित किया, जो कभी ट्रंप और मोदी के रिश्तों में दिखाई देती थी। ईरान युद्ध, भारतीय चालक दल वाले जहाजों को निशाना बनाए जाने और ओमान तट के पास अमेरिकी विमान के हमले में तीन भारतीयों की मौत जैसी घटनाओं ने भी स्थिति को और जटिल बना दिया। हालांकि हाल ही में फ्रांस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर जब ट्रंप और मोदी की मुलाकात हुई, तो ऐसा लगा कि दोनों देशों के रिश्तों में नाटकीय बदलाव आ गया है। गौरतलब है कि ट्रंप इससे पहले वर्ष 2020 में भारत आ चुके हैं। उस समय उनका भव्य स्वागत हुआ था और देशभर में 'नमस्ते ट्रंप' के बैनर लगाए गए थे। भारत यात्रा के संकेतों के अलावा जो बात सबसे अधिक चर्चा में रही, वह थी प्रधानमंत्री मोदी के लिए ट्रंप की प्रशंसा। तनाव को कमतर बताते हुए ट्रंप ने कहा कि जब तक वह राष्ट्रपति है-भारत को व्हाइट हाउस में एक महान मित्र मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को महान नेता 'बहुत मजबूत व्यक्ति, आकर्षक व्यक्तित्व वाला और बेहद दृढ़' बताया तथा यह भी कहा कि अगर कोई भारत पर हमला करता है तो वह भारत के साथ खड़े होंगे। अगर यह भारत के लिए अच्छी खबर है और ट्रंप ने मोदी तथा भारत के प्रति अपनी एकजुटता पूरी ताकत से दिखाई, तो वहीं अमेरिका के सहयोगी देश इटली के मामले में उनका रवैया पूरी तरह असहज करने वाला रहा। यहीं से सवाल उठता है, आखिर उनके व्यवहार में समस्या क्या है? एक बार फिर जी-7 सम्मेलन की ओर लौटते हैं, जहां ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा-उन्होंने मुझसे तस्वीर खिंचवाने की गुजारिश की। वह मेरे साथ तस्वीर चाहती थी। मैं तस्वीर नहीं खिंचवाता लेकिन मुझे उनके लिए बुरा लगा। रिपोर्टों के अनुसार जी-7 बैठक के दौरान मेलोनी ने ट्रंप से कहा था कि उन्हें शिकायत करना बंद करना चाहिए और यह कहना बंद करना चाहिए कि पश्चिमी सहयोगियों ने उन्हें छोड़ दिया है। ट्रंप की -तस्वीर के लिए गिड़गिड़ाने' वाली टिप्पणी क्या मेलोनी द्वारा उन्हें आईना दिखाने की प्रतिक्रिया थी, यह कहना मुश्किल है लेकिन ट्रंप की यह टिप्पणी किसी भी तरह उचित नहीं ठहराई जा सकती। बल्कि इसकी आलोचना होनी चाहिए। इटली ने इसका जवाब दिया और मेलोनी ने खुद ट्रंप पर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में कहा-डोनाल्ड ट्रंप के बयान पूरी तरह मनगढ़ंत है। मैं सचमुच हैरान हूं। मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ इस तरह व्यवहार क्यों करते हैं। और यह पहली बार नहीं है। उन्होंने आगे कहा-एक बात उन्हें याद रखनी चाहिए न तो मैंने और न ही इटली ने कभी किसी से गिड़गिड़ाकर कुछ मांगा है। मेलोनी सरकार ने इससे भी आगे बढ़कर कदम उठाया। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने ट्रंप की टिप्पणी से उपजे सरकारी आक्रोश को दर्शाते हुए अपनी प्रस्तावित अमेरिका यात्रा रद्द कर दी। दूसरे शब्दों में अगर मान भी लिया जाए कि मेलोनी ट्रंप के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहती थीं, तो भी वह किसी सरकार प्रमुख के लिए ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अगर वह खुद को सर्वशक्तिमान समझना पसंद करते हैं, तो क्या उन्हें यह अधिकार दूसरों की कीमत पर मिलना चाहिए? क्या कोई राजनीतिक बढ़त हासिल करना या पलटवार करना-जैसा कि ट्रंप अक्सर करते हैं क्या मर्यादा की सीमा से नीचे गिरने जैसा नहीं है? क्या दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति को अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर नहीं करना चाहिए? क्या ट्रंप जैसे नेता के लिए विश्व के अन्य नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करना और उनका अपमान करना उचित है? इसका उत्तर केवल एक शब्द में है, नहीं। और वह भी बड़े अक्षरों में। भारत में भी एक अलग तरह का नाटक सामने आ रहा है ऐसा नाटक, जिसमें श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुसार देखें तो देवी-देवताओं का भी अपमान हो रहा है। कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन था। स्वाभाविक रूप से जश्न की तैयारियां होनी थीं। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस अवसर को एक अलग दिशा दे दी और एक स्वयं को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले नेता को धार्मिक पहचान देने की कोशिश की। युवा कांग्रेस के नेताओं ने गांधी की तस्वीर लगाकर उसका पूजन किया और उस चित्र पर दूध चढ़ाया। इससे भी आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दर्शाया गया एक हाथ में फरसा और दूसरे हाथ में संविधान की प्रति।

यानी धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़ दिया गया। रिकॉर्ड के लिए परशुराम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते है और उन्हें ऋषि, योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें अपना फरसा भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। वे युद्धकला और अस्त्र-शस्त्रों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत में उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण सहित कई योद्धाओं को शिक्षा दी थी। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो 2024 के आम चुनावों में राहुल गांधी ने भारतीय संविधान को प्रमुख मुद्दा बनाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो वह संविधान को बदलने और दोबारा लिखने का प्रयास करेगी। गांधी जिस छोटी प्रति वाले संविधान को हर जगह अपने साथ रखते थे, उसने राजनीतिक संदेश के रूप में व्यापक प्रभाव पैदा किया। भाजपा के '400 पार' के दावे के बावजूद वह लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। लेकिन इन सबके बावजूद अब राजनीतिक तलवारें खिंच गई है। राहुल गांधी को भगवान के रूप में प्रस्तुत किए जाने को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 'हिन्दू आस्था का अपमान' किया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा -हिन्दुओं का अपमान करो और वोट बैंक से तालियां हासिल करो, यही उनकी राजनीति रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत करने के लिए माफी मांगने की मांग की। भाजपा के अन्य नेताओं ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भगवान परशुराम का अपमान किया है। इन सब से अलग हटकर देखें तो कांग्रेस जैसी अनुभवी राजनीतिक दल द्वारा किया गया यह कृत्य पूरी तरह अनुचित है।

आज स्थिति यह है कि भारत में हिंदू और मुसलमान भले ही साथ रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों समुदाय एक-दूसरे के खिलाफ खड़े किए जा रहे हैं। यह वही मुद्दा है, जिस पर राहुल गांधी अक्सर बोलते रहे हैं। याद कीजिए उनका 'मोहब्बत की दुकान' वाला नारा जो काफी लोकप्रिय हुआ था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब उनकी ही पार्टी उन्हें भगवान के रूप में प्रस्तुत कर रही है और उनकी तस्वीर पर धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे है, तो क्या राहुल गांधी को ऐसे कृत्यों की निंदा नहीं करनी चाहिए? या फिर उन्हें अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को भाजपा की धर्म आधारित राजनीति के रास्ते पर चलने की अनुमति देनी चाहिए? समय की मांग है कि राजनीति प्रतीकों से ऊपर उठे और देश के सामने एक रचनात्मक एजेंडा रखे। नेताओं को भगवान के रूप में प्रस्तुत करने में समय और ऊर्जा नष्ट करने के बजाय देश के वास्तविक मुद्दों और भविष्य की दिशा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

शांति समझौते के बाद नई उम्मीदें और पुरानी चुनौतियां

मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते ने परमाणु विवाद को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। इस समझौते के बाद अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने घोषणा की है कि वह जल्द ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम का निरीक्षण फिर से शुरू करेगी। हालांकि निरीक्षण की प्रक्रिया, समय और दायरे को लेकर अभी भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि युद्धविराम के बावजूद परमाणु मुद्दे पर भरोसे की कमी अब भी बनी हुई है। आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ईरान में निरीक्षण अवश्य होंगे। उन्होंने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम को कम संवर्धित करने (डाउन-ब्लेंडिंग) की प्रक्रिया आईएईए की निगरानी में होगी। एजेंसी अब ईरानी अधिकारियों के साथ निरीक्षण की तिथियों, प्रक्रियाओं और स्थानों को अंतिम रूप देने पर काम कर रही है। हालांकि ईरान ने इस मुद्दे पर कुछ अलग संकेत दिए हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक निरीक्षकों की पहुंच केवल अंतिम समझौते के तहत ही संभव होगी। उनका कहना है कि जब तक अमेरिका सभी प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में व्यावहारिक कदम नहीं उठाता, तब तक संवेदनशील स्थलों तक पहुंच का प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया के माध्यम से तथ्यों को थोपने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच पिछले सप्ताह 14 सूत्रीय प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर एक व्यापक और अंतिम समझौता करने का लक्ष्य रखा है। इसमें ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार के भविष्य, परमाणु गतिविधियों की निगरानी तथा प्रतिबंधों में राहत जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। समझौते में यह भी कहा गया है कि न्यूनतम स्तर पर उच्च संवर्धित यूरेनियम को ईरान में ही आईएईए की निगरानी में कम संवर्धित किया जाएगा। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन की यात्रा के दौरान स्पष्ट किया कि अमेरिका ऐसा कोई भी समझौता नहीं करेगा जिससे खाड़ी क्षेत्र में उसके सहयोगी देशों की सुरक्षा प्रभावित हो। उन्होंने कहा कि यदि ईरान गंभीरता के साथ समझौता करना चाहता है तो अमेरिका इसके लिए तैयार है, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। उन्होंने संकेत दिया कि दोनों देशों के वार्ताकार इस महीने के अंत तक स्विट्जरलैंड में फिर मिल सकते हैं। शांति समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू होर्मुज जलडमरूमध्य से भी जुड़ा है। समझौते के अनुसार ईरान इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से जहाजों के सुरक्षित आवागमन की अनुमति देगा, जबकि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए नौसैनिक अवरोध को हटाएगा। इस घोषणा के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में राहत देखने को मिली और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 75 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई। संयुक्त राष्ट्र ने भी पुष्टि की है कि युद्ध के कारण फंसे हजारों नाविकों को निकालने के लिए कुछ जहाज इस मार्ग से सुरक्षित रूप से गुजर चुके हैं। हालांकि परमाणु निरीक्षण को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ दिन पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया था कि ईरान ने आईएईए निरीक्षकों को वापस आने की सहमति दे दी है। लेकिन अगले ही दिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि इस विषय पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई है और अमेरिकी हमलों में क्षतिग्रस्त परमाणु स्थलों तक निरीक्षकों को पहुंच देने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इन विरोधाभासी बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए आईएईए प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों देशों के राष्ट्रपतियों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि परमाणु गतिविधियों की निगरानी आईएईए करेगा। उनके अनुसार निरीक्षण कुछ दिनों बाद हो या एक सप्ताह बाद, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निगरानी प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय रहा है। आईएईए की हालिया रिपोर्ट के अनुसार एजेंसी के निरीक्षकों को इस महीने बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का दौरा करने की अनुमति मिली थी, लेकिन उन्हें उन संवेदनशील स्थलों तक पहुंच नहीं दी गई जिन्हें पिछले वर्ष अमेरिका ने बमबारी में निशाना बनाया था। इसके कारण एजेंसी फिलहाल यह नहीं बता पा रही है कि ईरान के पास वर्तमान में कितना संवर्धित यूरेनियम है, वह कहां रखा गया है और क्या ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की गतिविधियां वास्तव में रोक दी हैं। युद्ध शुरू होने से पहले आईएईए ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम 60 प्रतिशत तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद था।

यदि इसे 90 प्रतिशत तक संवर्धित किया जाए तो सैद्धांतिक रूप से इससे लगभग दस परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। हालांकि ईरान लगातार यह दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। वर्तमान विवाद की जड़ 2015 का परमाणु समझौता भी है। उस समय अमेरिका और पांच अन्य विश्व शक्तियों के साथ हुए समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कई प्रतिबंध स्वीकार किए थे और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत मिली थी। लेकिन 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया और ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके जवाब में ईरान ने धीरे-धीरे समझौते की कई शर्तों का उल्लंघन करते हुए यूरेनियम संवर्धन बढ़ा दिया। आज की स्थिति में अमेरिका और ईरान के बीच हुआ प्रारंभिक समझौता एक नई शुरुआत का संकेत देता है, लेकिन स्थायी समाधान की राह अभी भी कठिन है। यदि आईएईए को स्वतंत्र और प्रभावी निरीक्षण की अनुमति मिलती है तथा दोनों पक्ष अपने वादों का पालन करते हैं, तो परमाणु संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

लेकिन यदि राजनीतिक अविश्वास और आरोप-प्रत्यारोप जारी रहे, तो यह समझौता भी अतीत के कई असफल प्रयासों की तरह अधूरा साबित हो सकता है। इसलिए आने वाले 60 दिन न केवल अमेरिका और ईरान, बल्कि पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत निर्णायक माने जा रहे हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार घाती ने कदना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार घाती, मो0 : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/[illegible])

यौम-ए-आशूरा पर जनपदभर में निकले ताजिया जुलूस, इमाम हुसैन की शहादत को किया गया याद

कुशीनगर।

मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम-ए-आशूरा शुक्रवार को जनपद कुशीनगर में गम, अकीदत और श्रद्धा के साथ मनाई गई। पैगंबर-ए-इस्लाम हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की कर्बला में दी गई महान शहादत की याद में जिले के विभिन्न नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ताजिया जुलूस निकाले गए तथा मजलिसों, मातमी कार्यक्रमों और फातिहाख्वानी का आयोजन किया गया। जनपद मुख्यालय पडरौना सहित कसया, कुशीनगर, खट्टा, सुकरौली, रामकोला, मिश्रौली, दुदही, तमकुहीराज, तमकुही रोड, पटहेरवा, फाजिलनगर, खड्डा, कप्तानगंज, सेवरही तथा आसपास के क्षेत्रों में अकीदतमंदों ने बड़ी संख्या में यौम-ए-आशूरा के कार्यक्रमों में भाग लिया। विभिन्न इमामबाड़ों और कर्बला स्थलों पर ताजिए पहुंचाए गए, जहां लोगों ने शहीद-ए-कर्बला को खिराज-ए-अकीदत पेश की। रविन्द्र नगर धूस क्षेत्र के सिधुआं बांगर भाठ स्थित ऐतिहासिक कर्बला पर दूर-दराज के गांवों से ताजिए पहुंचने का सिलसिला दिनभर जारी रहा। सिधुआं बांगर भाठ, चौपरिया, पलिया, धर्मपुर बुजुर्ग, धर्मपुर खुर्द, सोहनरिया, साढ़ी खुर्द, बैजनाथपुर, बंजारा पट्टी समेत कई ग्राम सभाओं के ताजिए कर्बला स्थल पर पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने फातिहा पढ़कर कर्बला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मजलिसों को संबोधित करते हुए उलेमा और धर्मगुरुओं ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन ने अन्याय, अत्याचार और असत्य के सामने झुकने के बजाय अपने परिवार और साथियों सहित शहादत को स्वीकार कर इंसानियत को अमर संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कर्बला की घटना पूरी मानवता को सत्य, न्याय, त्याग और मानव मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। यौम-ए-आशूरा के अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सबील लगाकर लोगों को शर्बत और पानी वितरित किया गया। मातमी जुलूसों में शामिल लोगों ने इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानी को याद करते हुए गम का इजहार किया तथा अमन, भाईचारे और इंसानियत की सलामती के लिए दुआएं कीं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मगुरु तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। चौपरिया ग्राम सभा के प्रधान असलम अंसारी, मोहम्मद आजम, मोहम्मद आलम, अकरम अंसारी, रिजवान अहमद, मजहर, अरमान, अलाउद्दीन सहित अनेक लोग कार्यक्रमों में शामिल हुए। मुहर्रम पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैद रहा। जनपद के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार भ्रमण कर जुलूस मार्गों और कर्बला स्थलों की निगरानी की। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी और मोबाइल पुलिस टीमों की भी सहायता ली गई। यौम-ए-आशूरा के अवसर पर जनपदभर में लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया। श्रद्धालुओं ने कहा कि कर्बला की कुर्बानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा सत्य, इंसाफ और मानवता की राह पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी।

कर्बला के शहीदों को खिराज-ए-अकीदत, कुशीनगर में गम और श्रद्धा के साथ मनाया गया यौम-ए-आशूरा

हज़रत हुसैन की सदाओं से गूंजा भटनी नगर, शान से लहराया तिरंगा

खिलाड़ियों ने दिखाए हैरतअंगेज़ करतब, सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस रही मुस्तैद

भटनी देवरिया। शुक्रवार को मोहर्रम की दसवीं (यौमे आशूरा) पर भटनी नगर में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में अकीदतमंदों ने ताज़िया जुलूस खूब निकाला। जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर या हुसैन की सदाओं के साथ इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित की। नगर की सड़कें दिन भर धार्मिक जोश और अकीदत के माहौल से गूंजती रहीं। जुलूस नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ रामलीला मैदान, गांधी चौक, मुख्य बाजार, 116 नंबर रेलवे क्रॉसिंग होते हुए रेलवे खेल मैदान पहुंचा। इस दौरान विभिन्न अखाड़ों के खिलाड़ियों ने लाठी, बनैती सहित कई हैरतअंगेज़ करतब प्रस्तुत किए। खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने उपस्थित लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। कई युवाओं ने आग के करतब, शरीर पर सुई और अन्य पारंपरिक प्रदर्शन भी किए। जुलूस में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पूरे सम्मान और शान से लहराता रहा। साथ ही इस्लामी झंडे भी आकर्षण का केंद्र रहे। पूरे मार्ग पर लोगों ने जगह-जगह जुलूस का स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारी निरीक्षक मृत्युंजय राय पुलिस बल के साथ शुरू से अंत तक पूरी तरह मुस्तैद रहे। पुलिस प्रशासन ने जुलूस को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराया। रेलवे खेल मैदान में क्षेत्र के विभिन्न गांवों और नगर की ताजियाओं का प्रदर्शन भी हुआ। ताजियाओं की भी लोगों ने सराहना की। मोहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें धार्मिक आस्था, भाईचारे और अनुशासन की मिसाल देखने को मिली।

अतिक्रमण व भूमि विवादों के विरोध में आज श्रीरामजानकी मंदिर परिसर में होगा विशाल धरना, साधु-संत करेंगे हनुमान चालीसा पाठ

नेबुआ नौरंगिया,कुशीनगर। विशुनपुरा ब्लॉक क्षेत्र स्थित श्रीरामजानकी मंदिर मनिकौरा परिसर में 27 जून को अतिक्रमण, भूमि विवादों और राजस्व संबंधी समस्याओं को लेकर विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश मंत्री राजन जायसवाल के नेतृत्व में होने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु-संतों और क्षेत्रीय लोगों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह नौ बजे सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ होगी। आयोजकों के अनुसार धरने में श्रीरामजानकी मंदिर मनिकौरा तथा ग्राम सभा पड़री महदेवा कोट मां स्थान की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग प्रमुखता से उठाई जाएगी। साथ ही भूमि विवादों के शीघ्र निस्तारण, पट्टाधारियों को उनकी भूमि पर कब्जा दिलाने तथा कथित भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। धरना-प्रदर्शन में विश्व हिंदू महासंघ के वरिष्ठ पदाधिकारी नरेंद्र मिश्र के आवासीय पट्टे पर कब्जा दिलाने, श्रीराम हनुमान सेवा दल के जिलाध्यक्ष श्यामबदन की कास्तकारी भूमि का सीमांकन कराकर अतिक्रमण हटाने तथा ग्राम सभा माघी कोठिलवा के पट्टाधारियों को उनकी भूमि का अधिकार दिलाने की मांग भी रखी जाएगी। आयोजकों ने कुछ पुलिस कर्मियों पर कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने की बात कही है। इसके अलावा पिपरा बुजुर्ग स्थित प्राचीन श्रीरामजानकी मंदिर के पोखरे की भूमि पर हुए कथित अवैध कब्जे को हटाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश मंत्री राजन जायसवाल ने क्षेत्र के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन भूमि, मंदिरों और पट्टाधारियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित किया जा रहा है।

एक सप्ताह से जला है ट्रांसफार्मर

अंधेरे में डूबा मिश्रौली धूप, ग्रामीणों में आक्रोश

भटनी देवरिया। भटनी क्षेत्र के ग्राम मिश्रौली धूप में पिछले एक सप्ताह से बिजली का ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण पूरा गांव भीषण बिजली संकट से जूझ रहा है। लगातार विद्युत आपूर्ति ठप रहने से ग्रामीणों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। भीषण गर्मी और उमस के बीच लोगों को दिन-रात भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रांसफार्मर जलने की सूचना बिजली विभाग के अधिकारियों को कई बार दी जा चुकी है, लेकिन अब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है। विभाग की ओर से भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बिजली न होने से पेयजल की समस्या भी गंभीर हो गई है। घरों में लगे सबमर्सिबल और पानी की मोटर बंद पड़ी हैं, वहीं बच्चों की पढ़ाई, मोबाइल चार्जिंग तथा छोटे कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं। रात में अंधेरा रहने से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक दिक्कत उठानी पड़ रही है।

सीएम योगी का जनता दर्शन में सख्त निर्देश - समस्याओं का शीघ्र समाधान कराएं अधिकारी

गोरखपुर। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की हर समस्या का शीघ्र समाधान कराएं। लोगों की शिकायतों को संवेदनशीलता से लेकर संतुष्टिप्रद निस्तारण सुनिश्चित कराने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जनता दर्शन में पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करिए। सरकार सबकी समस्या पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी। शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठाए गए लोगो तक पहुंचकर मुख्यमंत्री ने सबकी समस्याएं सुनीं और उनके प्रार्थना पत्रों को पास में खड़े अधिकारियों को हस्तगत कर समस्या समाधान हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सबकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। जनता दर्शन में हर बार की तरह कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। हृदय रोग से पीड़ित एक महिला से उन्होंने कहा कि इलाज के लिए उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीएम योगी ने जमीन कब्जा से जुड़ी शिकायतों पर अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में त्वरित और कड़े कदम उठाए जाएं। जबरन जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

विरासत और विकास के समन्वय से बदलेगी देवरिया की सूरत, बरहज और रुद्रपुर को 456 करोड़ की सौगात

देवरिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 106 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

सोनूघाट से बरहज तक बनेगा 172 करोड़ का फोरलेन

कानून व्यवस्था पर कड़ा रुख—उत्सवों में उपद्रव करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे

जनपद की विकास यात्रा को नया आयाम देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बरहज तहसील क्षेत्र के बरांव में आयोजित एक भव्य समारोह में देवरिया को 456.38 करोड़ की 106 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात सौंपी। मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट और विकास भवन द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना के तहत बटन दबाकर संयुक्त रूप से बरहज और रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी 64.94 करोड़ की 25 तैयार परियोजनाओं का लोकार्पण किया तथा 391.44 करोड़ की लागत वाली 81 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देवरिया महर्षि देवराहा बाबा की पावन तपोस्थली और बाबा राघवदास जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की संघर्ष भूमि है, जिसे अब गौरवशाली अतीत के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे से जोड़ा जा रहा है।

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, इस संपूर्ण निवेश में सबसे बड़ा हिस्सा बरहज विधानसभा क्षेत्र को मिला है, जहां 331.43 करोड़ की लागत से कुल 33 परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। इसमें 28.88 करोड़ के पूर्ण हो चुके 10 कार्य शामिल हैं, जबकि 302.55 करोड़ की 23 नई योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसमें 172 करोड़ की लागत से बनने वाला सोनूघाट-बरहज फोरलेन मार्ग प्रमुख है। इसी तरह रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 124.95 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसके तहत 36.06 करोड़ की 15 परियोजनाओं का लोकार्पण और 88.89 करोड़ की 58 नई योजनाओं की नींव रखी गई है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के व्यापारिक इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि बरहज को केवल बेहतरीन सड़क मार्ग से ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में जलमार्ग से भी जोड़ा जाएगा ताकि स्थानीय कृषि व व्यापारिक उत्पादों को सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार मिल सके। उन्होंने सरकार की वित्तीय कार्यकुशलता का उदाहरण देते हुए बताया कि 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण 11,200 करोड़ की लागत में पूर्ण कराकर बड़े पैमाने पर सरकारी धन की बचत भी की गई है। शासन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने सुरक्षा और सुशासन के मुद्दे पर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति प्रभावी है और उत्सवपूर्ण माहौल में किसी को भी उपद्रव करने या जनआस्था के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हाल ही में संपन्न हुई आरक्षी भर्ती परीक्षा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां की गई हैं, क्योंकि निष्पक्ष अवसर पाना युवाओं का बुनियादी अधिकार है। उन्होंने बताया कि प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी बनाने में कृषि क्षेत्र का बड़ा योगदान है और अब तक करीब 65 लाख युवाओं को विभिन्न निवेश प्रक्रियाओं से जोड़ा जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकायों और ग्राम प्रधानों से राष्ट्रीय दायित्व निभाते हुए यह सुनिश्चित करने की अपील की कि ग्रामीण अंचल में कोई भी पात्र व्यक्ति आवास, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, बिजली और स्वच्छ पानी जैसी शासकीय योजनाओं से वंचित न रहे। जनसभा से पूर्व मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और बाल विकास परियोजना के तहत दो बच्चों का अन्नप्राशन कराया। मंच से उन्होंने कुल 10 लाभार्थियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के स्वीकृति पत्र सौंपे, जिनमें संगीता देवी व गुड़िया यादव को अंत्योदय राशन कार्ड, प्रमोद प्रसाद व अरविंद तिवारी को निर्विवाद वरासत प्रमाण पत्र, और अखिलेश व नरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत 5-5 लाख के चेक शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रायमंत्री कमलेश पासवान, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, रायमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, बरहज विधायक दीपक कुमार मिश्रा शाका, रुद्रपुर विधायक जयप्रकाश निषाद और सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी सहित जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

दिल्ली प्रशासन में बड़ा फेरबदल - एलजी संधु ने 57 अफसरों को किया इधर से उधर, तबादले और नई पोस्टिंग के आदेश जारी

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा फेरबदल करते हुए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने 57 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नई पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। इस व्यापक फेरबदल में 14 एडहॉक दानिक्स और 43 वरिष्ठ आईएएस व दानिक्स अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिसका सीधा असर दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं, जलापूर्ति (डीजेबी) और राजस्व विभाग के कामकाज पर पड़ेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे, ताकि जनहित के कार्यों में कोई देरी न हो। प्रशासनिक स्तर पर सबसे बड़ा बदलाव अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) स्तर पर देखा गया है। विपुल पाठक (आईएएस 1992) को समाज कल्याण के साथ-साथ अब महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी प्रकार, नवीन कुमार चौधरी (आईएएस 1994) को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (आईएफसी) के साथ सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। निखिल कुमार (आईएएस 2010) अब दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के साथ-साथ आईटी विभाग के सचिव की भूमिका भी निभाएंगे। दिल्ली की जनता के लिए सबसे राहत की बात यह हो सकती है कि स्वास्थ्य एवं जल बोर्ड जैसे विभागों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। वैभव रिछारिया (दानिक्स 2013) और किरण कुमार सिंह (दानिक्स 2014), जो पहले मंत्रियों के सचिव के रूप में तैनात थे, उन्हें अब दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में निदेशक बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग में यश चौधरी (आईएएस 2017) को अतिरिक्त वित्तीय शक्तियां दी गई है, ताकि विभागीय खर्चों और नई योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आ सके। इसके अलावा, मेकला चैतन्य प्रसाद (आईएएस 2015) को दक्षिण-पश्चिम जिले के डीएम पद से हटाकर स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। राजस्व विभाग और जमीनी प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए, बड़ी संख्या में एसडीएम बदले गए हैं। यश पाल को पटपड़गंज से पटेल नगर और कुलदीप सिंह पाखा को मॉडल टाउन का एसडीएम नियुक्त किया गया है। इसी तरह, नितिन शाक्य को पटेल नगर से पटपड़गंज और अभिषेक खुशिया को कालका जगर से देवली का एसडीएम बनाया गया है। चुनाव कार्य और जेल प्रशासन में भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई है, जिसमें अजीत कुमार को मध्य दिल्ली का एसडीएम (चुनाव) और पवन कुमार को जेल अधीक्षक नियुक्त किया गया है। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) और महिला एवं बाल विकास विभाग में भी नई नियुक्तियां की गई हैं। जी सुधाकर (आईएएस 2012) को दिल्ली महिला आयोग का सदस्य सचिव बनाया गया है, जबकि पार्थेल प्रांजल लाहोरसिंह को महिला एवं बाल विकास विभाग में विशेष निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कदम शहर में महिला कल्याण योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में देखा जा रहा है। दिल्ली प्रशासन का मानना है कि इस फेरबदल से विभागों के बीच समन्वय बढ़ेगा और अटके हुए प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी। एलजी के आदेश में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि राजवीर सिंह और राजिंदर कुमार आहूजा जैसे अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति तक कामिक पदों (एसडीएम वेस्ट और एसडीएम नई दिल्ली) पर बने रहेंगे, जिससे प्रशासनिक निरंतरता बनी रहे। सभी स्थानांतरण आदेशों को तुरंत लागू करने के निर्देश दिया गया है।

दिल्ली सरकार 265 करोड़ के अपग्रेड के साथ सभी 75 सीएम श्री स्कूलों को आधुनिक बनाएगी

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी 75 सीएम श्री स्कूलों के लिए ?265 करोड़ के निवेश के साथ एक व्यापक आधुनिकीकरण योजना की घोषणा की है। इस पहल का मकसद स्कूलों में शिक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना और छात्रों के लिए सीखने की सुविधाओं को बेहतर बनाना है। सरकार के अनुसार, इस प्रोजेक्ट में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक खेल सुविधाएं, साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क, सीसीटीवी-आधारित सुरक्षा सिस्टम, बेहतर कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए सुलभ सुविधाएं शामिल होंगी। यह पहल राजधानी में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करते हुए सीखने के लिए एक आधुनिक, सुरक्षित और समावेशी माहौल बनाने की सरकार की कोशिशों का हिस्सा है। उम्मीद है कि अपग्रेड किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से छात्रों के लिए पढ़ाई-लिखाई और पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों (एक्स्ट्रा-करिकुलर) के अवसर बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि आधुनिकीकरण कार्यक्रम सीएम श्री स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर और सीखने के लिए बेहतर माहौल तैयार करके छात्रों के सर्वांगीण विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वेनेजुएला भूकंप में अब तक 235 की मौत -4300 से ज्यादा घायल

कराकस, वेनेजुएला । दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए दो भूकंप में अब तक 235 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। जबकि 4300 से ज्यादा लोग घायल है। वेनेजुएला में बुधवार यानी 25 जून को साल 1821 के काराबोबो युद्ध की याद में राष्ट्रीय अवकाश था। इसलिए ज्यादातर लोग घरों में थे और फीफा वर्ल्ड कप मैच देख रहे थे। इससे मलबे में दबने वालों की संख्या यादा होने की आशंका है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मलबे के अंदर से आवजें आ रही हैं। सरकार ने देर रात बताया कि 39 हजार से ज्यादा लोग लापता हैं। भूकंप की भयावहता की असल तस्वीर अभी आना बाकी है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप से 10 हजार से यादा लोगों के मारे जाने की 44 फीसदी आशंका है। वहीं, एक लाख लोगों के जान गंवाने की 30फीसदी आशंका है। इस आपदा से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को 9.5 लाख करोड़ रुपए के नुकसान हो सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने आपातकाल लगा दिया है।

अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाया तो लगेगा 100फीसदी टैरिफ, यूरोपीय देशों को ट्रंप की बड़ी चेतावनी

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है जो अमेरिकी कंपनियों की डिजिटल सेवाओं पर कर (टैक्स) लगाने की योजना बना रहे है। ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के माध्यम से चेतावनी दी कि यदि कोई देश अमेरिकी डिजिटल सेवाओं पर टैक्स लगाता है, तो उस देश से अमेरिका आने वाले सभी सामानों पर 100फीसदी टैरिफ (आयात शुल्क) लगाया जाएगा। ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि कुछ यूरोपीय देश अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल सेवा कर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके अनुसार, यह टैक्स खासतौर पर अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है। ट्रंप ने लिखा, यह बयान आधिकारिक चेतावनी माना जाए कि जो भी देश ऐसा टैक्स लगाएगा, उसके अमेरिका भेजे जाने वाले सभी

सामानों पर तुरंत 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि यह नया शुल्क पहले से हुए किसी भी व्यापार समझौते से ऊपर होगा। यानी अगर किसी देश के साथ पहले कोई व्यापारिक रियायत या समझौता हुआ है, तब भी यह 100 फीसदी शुल्क लागू किया जा सकता है। हालांकि ट्रंप ने किसी एक देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने खास तौर पर यूरोपीय देशों का जिक्र किया। माना जा रहा है कि उनका निशाना उन देशों पर है जो अमेरिकी टेक कंपनियों जैसे गूगल, मेटा, अमेजन और अन्य डिजिटल कंपनियों से अतिरिक्त टैक्स वसूलने की योजना बना रहे है।

ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के माध्यम से चेतावनी दी कि यदि कोई देश अमेरिकी डिजिटल सेवाओं पर टैक्स लगाता है, तो उस देश से अमेरिका आने वाले सभी सामानों पर 100फीसदी टैरिफ (आयात शुल्क) लगाया जाएगा।

4 जुलाई की समयसीमा से पहले बढ़ी हलचल

यह कड़ी चेतावनी ऐसे समय में आई है जब यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण टैरिफ सौदे को मंजूरी देने की 4 जुलाई की समयसीमा नजदीक है। इस प्रस्तावित सौदे के तहत अधिकांश यूरोपीय निर्यात पर टैरिफ को 15फीसदी तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रंप की इस नई धमकी ने आगामी व्यापार वार्ताओं में तनाव बढ़ा दिया है।

गहरी खाई में गिरी पिकअप गाड़ी, मां-बेटे सहित छह लोगों की मौत, वायरल वीडियो

रामपुर बुशहर। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में मां-बेटे समेत छह लोगों की मौत हो गई है। पुलिस थाना रामपुर के तहत आने वाले दुर्गम क्षेत्र कशापाट में एक पिकअप गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में गाड़ी में सवार मां-बेटे और चालक समेत सभी छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा शुक्रवार अपराह्न 4:35 बजे छछोल-कशापाट मार्ग पर पेश आया। बताया जा रहा है कि चालक दूध की सप्लाई देकर लौट रहा था और रास्ते में पांच लोगों ने लिफ्ट ली थी। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने शवों को सड़क तक पहुंचाया। डीएसपी ने बताया कि शवों

को खनेरी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के बाद कशापाट पंचायत में शोक की लहर दौड़ गई है। रामपुर के एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतकों के परिवार वालों को फौरी राहत राशि जारी की जाएगी।हादसे के समय पिकअप में बैठी महिला फेसबुक पर लाइव हुई थी। महिला पिकअप में बैठी सवारियों को अपना ननिहाल दिखा रही थी। महिला की बातचीत के दौरान ही चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया। इससे गाड़ी से नीचे गिर गई। वीडियो में यात्रियों की चीख-पुकार साफ सुनी जा सकती है। हादसे का दिल झकझोर देने वाला यह वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आशा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल डिंगढ़ में बतौर हिंदी की प्रवक्ता तैनात थी।

मोदी कैबिनेट और बीजेपी संगठन में जल्द होगा बंपर फेरबदल

नई दिल्ली ।दिल्ली की राजनीति गलियारों में बड़ी हलचल चल रही है। ऐसी खबरें सामने आ रही है कि मोदी कैबिनेट में बदलाव होने वाला है। आगामी 2029 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए टीम के नए रुप को तैयार किया जा रहा है। ऐसे में

उम्मीद है कि पार्टी में कुछ फेरबदल किए जा सकता है और कुछ नए चेहरों को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा खराब परफॉर्मेंस वाले कुछ मंत्रियों की विदाई भी तय मानी जा रही है। पिछले कुछ समय में पार्टी में कुछ नए चेहरे जुड़े है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे नाम नए कैबिनेट मंत्रियों की रेस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल से टीएमसी से दूरी बना चुके कुछ खास सांसद जैसे सुदीप बंद्योपाध्याय, शताब्दी राय और काकोली घोष जैसे कद्दावर नेताओं के नामों पर गंभीरता से विचार हो रहा है। ऐसी उम्मीद जताई दवा रही है कि इनमें से भी किसी को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसी के साथ ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली से कुछ मंत्रियों को उनके पदों से हटाया जा सकता है। पार्टी पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा जैसे सीनियर नेताओं को वापिस भेज कर चुनाव सुधारने की कोशिश करने वाली है,ताकि युवाओं को आगे लाया जा सकेगा। इसके अलावा पार्टी द्वारा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। ऐसी उम्मीद है कि पार्टी में एक- दो नई महिला उपाध्यक्षों की एंट्री हो सकती है। इसके साथ ही, पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश) और पूर्वोत्तर (त्रिपुरा) के सीनियर नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर क्षेत्रीय असंतोष को दूर करने की कोशिश की जाएगी।

अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे का भारी विरोध, संतों ने जलाया पुतला, लगाये केजरीवाल वापस जाओ के नारे

दरअसल, केजरीवाल ने वर्षों पहले कथित रूप से राम मंदिर की जगह स्कूल, अस्पताल और शौचालय बनाने जैसा विवादास्पद बयान दिया था।

अयोध्या । आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या दौरे पर पहुँचे तो उनका स्वागत विरोध प्रदर्शनों और केजरीवाल वापस जाओ जैसे नारों से हुआ। दरअसल, केजरीवाल ने वर्षों पहले कथित रूप से राम मंदिर की जगह स्कूल, अस्पताल और शौचालय बनाने जैसा विवादास्पद बयान दिया था। केजरीवाल जब रामनगरी पहुंचे तो संत समाज और कई स्थानीय संगठनों ने उनका जोरदार विरोध किया। जगह जगह केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगे और संतों ने उनका पुतला जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। संतों का कहना था कि जिन्होंने कभी राम मंदिर निर्माण की भावना का विरोध किया, आज वही राजनीतिक लाभ के लिए अयोध्या की धरती पर आकर श्रद्धा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध कर रहे साधु संतों ने आरोप लगाया कि यह दौरा आस्था से अधिक राजनीति से प्रेरित है । हालांकि भारी विरोध के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने रामलला के दर्शन किए और बाद में प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। उनके साथ पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया।

बैरियर तोड़ उत्तराखंड में किया प्रवेश- अज्ञात निहंग सिखों पर हत्या के प्रयास समेत गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज

विकासनगर(देहरादून) । चंडीगढ़ से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए निहंग सिखों के पहले जत्थे के बृहस्पतिवार रात कुल्हाल बैरियर तोड़कर उत्तराखंड में प्रवेश करने के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस का आरोप है कि बैरिकेडिंग तोड़ने, पुलिसकर्मियों पर वाहन चढ़ाने का प्रयास करने, हथियार लहराकर भय फैलाने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं हुई है। एसपी देहात पंकज गैरोला ने बताया कि कर्णप्रयाग में निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद हुआ था। सोशल मीडिया पर 25 जून को बड़ी संख्या में निहंग सिखों के कर्णप्रयाग पहुंचने की अपील की गई थी। इसके मद्देनजर कुल्हाल बैरियर पर पुलिस, पीएसी और आईटीबीपी की तैनाती की गई थी। पुलिस ने जत्थे से बिना हथियार और छोटे-छोटे समूहों में यात्रा करने का अनुरोध किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। वार्ता विफल होने के बाद निहंग सिख बैरिकेडिंग तक पहुंचे और तलवार, कृपाण, फरसे, भाले व अन्य हथियार लहराते हुए बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल गए। इस दौरान बैरिकेडिंग के आसपास खड़े वाहनों को भी क्षति पहुंचाई गई और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया, जिससे मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। अज्ञात निहंग सिखों के खिलाफ हत्या के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा डालने, लोक सेवक पर हमला, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आपराधिक बल प्रयोग और लोगों में भय का माहौल बनाने जैसे आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधान गो बैक अभियान का किया एलान; 28 जून को जंतर-मंतर पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने छात्रों, किसानों और नागरिक से 28 जून को जंतर-मंतर पर जुड़ने का आह्वान किया।

अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेगी

यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, दिपके ने कहा कि कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी रविवार को जंतर-मंतर पर 'प्रधान गो बैक' (प्रधान वापस जाओ) अभियान में शामिल होंगी। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगी। हालांकि, उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि अभियान में क्या-क्या शामिल होगा। सीजेपी के संस्थापक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि प्रधान इस्तीफा दे दें। इसके साथ ही कहा कि अगर वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें अक्षम प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाएगा। सीजेपी, जिसने एक डिजिटल व्यंग्य संगठन के रूप में शुरुआत की थी। परीक्षा में कथित अनियमितताओं और नीट पेपर लीक विवाद को लेकर प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 जून से जंतर-मंतर पर धरना दे रही है।

सोनम वांगचुक भी हड़ताल में होंगे शामिल

दिपके ने कहा कि एक सप्ताह बीत चुका है और धर्मेंद्र प्रधान ने अखबार लीक होने की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। सोनम वांगचुक रविवार से विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों की

आत्महत्याओं के लिए किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया जा रहा है। वहीं, वांगचुक जैसी एक शिक्षिक और वैज्ञानिक को भूख हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। वहीं, पहले ही 20 छात्र मर चुके है। दिपके ने आगे कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है। प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन छात्रों का खून उनके हाथों पर है। वह हमें आतंकवादी कह रहे थे, लेकिन असली आतंकवादी वह खुद हैं क्योंकि इन छात्रों की मौत का कारण वही है।

यह देश कब तक जवाबदेही के बिना चलता रहेगा?

प्रधान वापस जाओ विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायिक समिति सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करना चाहती है। उन्होंने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, किसान संघों और नागरिक समाज समूहों से रविवार को जंतर-मंतर पर आने का आह्वान किया। दिपके ने कहा, यह देश कब तक जवाबदेही के बिना चलता रहेगा? यह किस तरह का लोकतंत्र है? क्या यह अच्छी बात है कि इस सरकार में कोई इस्तीफा नहीं देता?

आत्महत्या करने वाले छात्रों के लिए मुआवजे की मांग

चीफ जस्टिस ऑफ जस्टिस (सीजेपी) के संस्थापक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रधान इस्तीफा दें, अन्यथा उन्हें छात्रों की मौत के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। अगर प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अक्षम साबित होंगे। दिपके ने आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की भी मांग की। इस मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर, दिपके ने कहा कि पार्टियों को अपने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर छात्रों के लिए आवाज उठानी चाहिए। इस सवाल पर कि क्या प्रधान के इस्तीफे के साथ ही मुख्य न्यायाधीश का आंदोलन समाप्त हो जाएगा, उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब देना अभी जल्दबाजी होगी। प्रधान के पद छोड़ने पर जनता का गुस्सा शांत हो जाएगा या नहीं, इस सवाल के जवाब में दिपके ने कहा, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर कुछ प्रदर्शनकारियों और स्वयंसेवकों पर गुंडों ने हमला किया था और पुलिस पर शिकायतें मिलने के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया, प्रदर्शनकारियों के लिए खाना लाने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक मामले में तो वे एक स्वयंसेवक के ससुराल तक घुस गए। हम पर हमला करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं जबकि पुलिस का कहना है कि उन्हें अदालती आदेश की जरूरत है। मुझे संदेह है कि यह सब पहले से योजनाबद्ध है।

ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत- कांग्रेस का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला; खेड़ा बोले- एक साल तक छिपाया वीरों का बलिदान

नई दिल्ली।

देश की राजनीति में राष्ट्रवाद और सैनिकों के सम्मान को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए छह जवानों के बलिदान को स्वीकार करने में पूरे एक साल की देरी कर दी। पार्टी ने इसे देश के नायकों का अपमान बताया है।

कांग्रेस ने लगाया एक साल तक बलिदान छिपाने का आरोप

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो सरकार खुद को राष्ट्रवाद के चोगे में

लपेट कर रखती है, उसी ने देश के वीर सपूतों को एक साल तक वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश के लिए शर्म की बात है। पवन खेड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान गंवाने वाले सभी छह सैन्य कर्मियों के नामों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के वो बहादुर बेटे है, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के सम्मान और हमारी बहनों के सिंदूर की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। खेड़ा ने कहा कि इन शहीदों के नाम राष्ट्रीय चेतना में दर्ज होने चाहिए थे और उनके परिवारों को देखना चाहिए था कि पूरा देश उनकी शहादत का सम्मान कर रहा है। लेकिन, भाजपा सरकार ने एक साल तक इस सच को देश से छिपा कर रखा।

"केंद्र सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर के छह शहीदों का नाम एक साल तक छिपाने का आरोप लगाया है। मई 2025 के इस ऑपरेशन में बलिदान हुए जवानों के नाम अब जाकर दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल की दीवार पर लिखे गए हैं, जिसे कांग्रेस ने सरकार का छद्म राष्ट्रवाद करार दिया है।

नेशनल वॉर मेमोरियल में दर्ज हुए नाम

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के इन छह जांबाजों के नाम दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल (राष्ट्रीय समर स्मारक) की दीवार पर सुनहरे अक्षरों में अंकित किए गए हैं। इनमें भारतीय सेना के पांच और वायुसेना का एक जवान शामिल है। सरकार ने ऑपरेशन के बाद पहली बार आधिकारिक तौर पर इन नामों को सार्वजनिक किया है। यह पूरा मामला मई 2025 का है, जब 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसी अभियान के दौरान देश के छह वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हाल ही में नेशनल वॉर मेमोरियल के त्याग चक्र की दीवार संख्या 38 पर इन शहीदों के नाम उनकी यूनिट के साथ लिखे गए हैं। स्मारक की दीवार पर जिन जांबाजों के नाम दर्ज हुए हैं, उनमें सेना के सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मुरली मुरलीनायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और भारतीय वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शामिल है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, इन नामों को हाल ही में मेमोरियल की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।

राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय व सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा

अयोध्या । राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज एफआईआर के बाद बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चम्पत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा ने अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि जांच की निष्पक्षता बनाए रखने और जांच पूरी होने तक यह कदम उठाया गया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास ने इस मामले में कहा कि उन्हें अब की स्थिति की कोई जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि चढ़ावा गबन मामले में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है। बता दें कि बृहस्पतिवार से ही चंपत राय के इस्तीफे की चर्चा थी। वहीं, कल रात चढ़ावा चोरी के मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। चढ़ावा चोरी प्रकरण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की तैयारी है, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। मामले में दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस जांच तेज कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार जांच में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट को भी शामिल किया जाएगा, ताकि सभी तथ्यों का समग्र परीक्षण हो सके। उधर, विपक्षी दल एफआईआर में किसी बड़े पदाधिकारी का नाम शामिल न किए जाने को लेकर सवाल उठा रहे है और जांच की निष्पक्षता पर आरोप लगा रहे है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी .